समावेशी इंटरनेट सूचकांक

द हिन्दू, (28 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit- EIU) द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक- 2019 (Inclusive Internet Index- 2019) प्रकाशित किया गया।
- यह इंडेक्स यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिये कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है।

उद्देश्य

- यह सूचकांक शोधकर्त्ताओं और नीति निर्माताओं को वो सूचनाएँ प्रदान करना है, जिनकी सहायता से विभिन्न वर्गों तक इंटरनेट का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- यह इंटरनेट से संबंधित निम्नलिखित चार आधारों पर विभिन्न देशों का आँकलन करता है:
- सुलभता (Accessibility)
- कम खर्च में उपलब्धता (Affordability)
- प्रासंगिकता (Relevance)
- तत्परता (Readiness)
- 100 देशों में स्वीडन प्रथम स्थान पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका है।
- भारत को 47वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। पड़ोसी देशों में चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका क्रमश: 42 77, 74, 72, 71, 58वें स्थान पर हैं।

''प्रणाम'' आयोग

टाइम्स ऑफ इंडिया, (28 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में प्रणाम आयोग की घोषणा की। यह घोषणा प्रणाम (Parents Responsibility and norms for Accountability and Monitoring) बिल के तहत की गयी है।

क्या है?

- इस बिल के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को अपने अभिभावकों तथा अविवाहित दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल करनी होगी, जिनके पास स्वयं की आय का कोई स्त्रोत नहीं है।
- इस बिल के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में माता-पिता या दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल न किये जाने की शिकायत मिलती है तो उस कर्मचारी के वेतन का 10 से 15% हिस्सा काटकर उसके माता-पिता अथवा दिव्यांग भाई-बहनों को दिया जायेगा।
- असम सरकार इस योजना को निजी कर्मचारियों तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू करने पर विचार कर रही है।
- इस बिल का उद्देश्य सरकार द्वारा वृद्ध माता-पिता तथा दिव्यांग भाई-बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है तथा उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह देश में इस प्रकार का पहला बिल है।

Committed To Excellence

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति

इकोनॉमिक टाइम्स, (28 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी प्रदान की है।
- इस नीति का उद्देश्य देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का प्रमुख केंद्र बनाना है।
- केंद्र सरकार का कहना है कि इससे वर्ष 2025 तक 65 लाख नौकरियों का सृजन होगा।
- भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार 168 अरब डॉलर का है। इसमें अधिकतर हिस्सेदारी सेवाओं की है, जबकि इसमें सॉफ्टवेयर उत्पादों का हिस्सा कम है। यह मात्र 7.1 अरब डॉलर है।
- अधिकतर सॉफ्टवेयर उत्पाद आयात किए जाते हैं। यही वजह है कि सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को 2025 तक देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र में एक बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य लेकर तैयार किया गया है।

क्रियान्वयन रणनीति और लक्ष्य

- इस नीति के अंतर्गत जिस रूपरेखा की परिकल्पना की गई है, उससे देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं और तौर-तरीकों के सूत्रीकरण की राह बनेगी।
- सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति (एनपीएसपी-2019) के सपने को हासिल करने के लिए इस नीति में निम्नलिखित पांच मिशन रखे गए हैं -
- बौद्धिक संपदा (आईपी) से संचालित होने वाले एक स्थायी भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को प्रोत्साहित करना, जिससे 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में दस गुना बढ़ोतरी तक पहुंचा जा सके।
- सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में 10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को पोषित करना, जिसमें टीयर-2 और टीयर-3 नगरों व शहरों में ऐसे 1000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी शामिल हैं। साथ ही 2025 तक सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर 35 लाख लोगों के लिए रोजगार निर्मित करना।

- सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए एक प्रतिभा समूह का निर्माण करना।
- इसके लिए ये किया जाएगा - (क) 1,000,000 सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को अतिरिक्त कुशलताओं से सुसज्जित करना (ख) 100,000 स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, और (ग) 10,000 विशेषीकृत पेशेवरों का निर्माण करना जो नेतृत्व प्रदान कर सकें।
- एकीकृत आईसीटी आधारभूत ढांचे, मार्केटिंग, इनक्यूबेशन, अनुसंधान व विकास / परीक्षण मंच और परामर्श सहयोग वाले 20 क्षेत्रवार व रणनीतिक रूप से स्थित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास क्लस्टर विकसित करते हुए एक क्लस्टर आधारित नवाचार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
- इस नीति की योजना और कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और उन्हें विकसित करने की दिशा में राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन की स्थापना की जाएगी जिसमें सरकार, शिक्षा समुदाय और उद्योग की भागीदारी होगी।

राष्ट्रीय खनिज नीति 2019

टाइम्स ऑफ इंडिया, (28 Feb.)

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी), 2019 को मंजूरी दे दी है।
- नई राष्ट्रीय खनिज नीति अधिक प्रभावी नियमन सुनिश्चित करेगी।
- यह खनन क्षेत्र के स्थायी विकास में सहायता प्रदान करेगी तथा इससे परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बेहतर समाधान में मदद मिलेगी।

उद्देश्य

- प्रभावी, अर्थपूर्ण और कार्यान्वयन-योग्य नीति का निर्माण करना है।
- इससे बेहतर पारदर्शिता, नियमन और कार्यान्वयन, संतुलित सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ दीर्घावधि खनन अभ्यासों को समर्थन मिलेगा।

National Mineral Policy, 2019

शामिल प्रावधान

- आरपी/पीएल धारकों के लिए पहले अस्वीकार के अधिकार की शुरूआत।
- अन्वेषण कार्य के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना।
- राजस्व-साझा के आधार पर समग्र आरपी-सह-पीएल-सह-एमएल के लिए नये क्षेत्रों में नीलामी।
- खनन कंपनियों में विलय और अधिग्रहण को प्रोत्साहन तथा खनन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए खनन-पट्टों के हस्तांतरण की अनुमति तथा समर्पित खनिज कॉरीडोर का निर्माण।

मुख्य बिंदु

- 2019 नीति में प्रस्ताव दिया गया है कि खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। इससे निजी क्षेत्र को खनन-संपत्ति अधिग्रहण के लिए वित्त पोषण प्राप्त होगा।
- यह भी उल्लेख किया गया है कि खनिज के लिए दीर्घकालिक आयात-निर्यात नीति के निर्माण से निजी क्षेत्र बेहतर नीतियां बनाने में सक्षम होगा और व्यापार में स्थिरता आएगी।
- नीति में निजी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए वैश्विक मानदंडों के आधार पर टैक्स, लेवी और रॉयल्टी को युक्तिसंगत बनाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में चर्चा में रहा समावेशी इंटरनेट निम्नलिखित में से किन आधारों पर निर्धारित किया गया है?

1. सुलभता
2. कम खर्च में उपलब्धता
3. प्रासंगिकता
4. तत्परता

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए-

(a) 1 और 4 (b) 1 और 2
(c) 1, 2 और 4 (b) उपर्युक्त सभी

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में प्रणाम बिल के तहत सिक्किम राज्य ने प्रणाम आयोग को गठित करने की घोषणा की।
2. प्रणाम बिल का उद्देश्य सरकार द्वारा वृद्ध माता-पिता तथा दिव्यांग भाई-बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

3. राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस नीति का उद्देश्य देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का प्रमुख केन्द्र बनाना है।
2. भारत विश्व में सॉफ्टवेयर उत्पाद निर्यात करने वाले शीर्ष तीन राष्ट्रों में शामिल है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

4. राष्ट्रीय खनिज नीति- 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इससे बेहतर पारदर्शिता, नियमन और कार्यान्वयन, संतुलित सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ दीर्घावधि खनन अभ्यासों को बल मिलेगा।
2. इस नीति के माध्यम से अन्वेषण कार्य के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (b) न तो 1, न ही 2

नोट : 26-27 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d), 3(c), 4(c), 5(c), 6(c), 7(c), 8(c) होगा।